

हम प्रदेश के उद्योग धंधों को वैश्विक.....

पेज 1 से जारी....

निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देने 2025 उद्योग वर्ष के रूप मनेगा: डॉ. यादव



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में भी टैक्सटाइल एवं गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उद्योगपतियों के लिए मध्यप्रदेश में निवेश कर अपने व्यापार-व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। मध्यप्रदेश में निवेश के हर पहलू का ध्यान रखा गया है।

मध्यप्रदेश प्यूचर रेडी प्रदेश है, यहाँ संभावनाओं के साथ सरकार का सहयोग एवं जनता का साथ है। आजादी के अनंतकाल को मध्य प्रदेश का भाग्योदयकाल बनाने के लिए हम प्रदेश के उद्योग धंधों को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के विजन पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए राज्य सरकार सतत प्रयासरत है। इस दिशा में रोजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिये प्रदेश के हर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की नई पहल शुरू की गई है। डॉ. यादव ने

कहा कि भोपाल में 7-8 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। मैं आपको प्रदेश में चल रही निवेश क्रांति का हिस्सा बनने का निमंत्रण देने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि मध्यप्रदेश में उपलब्ध अपार अवसरों का लाभ उठाते हुए विकसित भारत के साथ ही विकसित मध्यप्रदेश के विजन को साकार करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इको-सिस्टम अत्यंत अनुकूल

मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राज्य का इको-सिस्टम अत्यंत अनुकूल है। वृहद श्रेणी के गारमेंट उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में लागू विशेष रेडीमेड गारमेंट पॉलिसी में स्थाई पूंजी निवेश के 200 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन तैयार करने के लिए जबलपुर शहर में अति आधुनिक

स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की जा रही है और स्किल एवं क्लस्टर डेवलपमेंट में सहायता के लिए तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ भी एमओयू किया गया है। मध्यप्रदेश, देश में टैक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को सर्वोत्तम वित्तीय लाभ का पैकेज दे रहा है। उन्होंने कहा कि कॉटन की उपलब्धता, सस्ती भूमि और आकर्षक वित्तीय लाभों के कारण देश की बड़ी टैक्सटाइल कंपनियों मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रही हैं। यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र इंडीग्रेटेड मेगा टैक्सटाइल पार्क को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्रीज के 10 से अधिक आईएम तथा 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं की उपस्थिति मध्यप्रदेश में है। कर्मशियल व्हीकल्स निर्माण के लिए जरूरी आईएम तथा एनसीएलसी के भी कई बड़ी छोटी इकाइयां कार्यरत हैं। प्रदेश में ऑटो सेक्टर के लिए आवश्यक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर, द सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इस्टीट्यूट, बुदनी में और पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर ट्रेनिंग सेंटर एवं ऑटो टेस्टिंग ट्रैक नैट्रैक्स इत्यादि भी उपलब्ध है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स तथा इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपोनेंट्स राज्य सरकार के फोकस सेक्टर में सम्मिलित हैं तथा शीशू हर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए फोकस नीति भी लाई जा रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य शासन द्वारा इंदौर के निकट ई-वी डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है तथा प्रदेश में भी ई-वी कर्मशियल व्हीकल एवं टू व्हीलर, श्री व्हीलर का निर्माण किया जा रहा है।



मप्र है पीपुल्स फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेस्टीनेशन

डॉ. यादव ने कहा कि राज्य को खनिज-वन-जल और पर्यटन सम्पदा का भरपूर उपहार मिला है। उद्योगों की स्थापना और निवेश के लिए मध्यप्रदेश पीपुल्स फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेस्टीनेशन है। प्रदेश की अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी अच्छी है, प्रदेश के इंडस्ट्रियल कोरिडोरों से विभिन्न एक्सप्रेस-वे गुजर रहे हैं। प्रदेश विद्युत सरप्लस स्टेट है, %उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक की भी उपलब्धता है और यहाँ क्लीन व ग्रीन एनर्जी का भंडार है। राज्य में 320 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 10 फूड पार्क्स 5 आईटी एसईजेड, 2 स्पाइस पार्क्स, 2 मल्टी प्रोडक्ट सेज, तथा 2 प्लास्टिक पार्क्स हैं। नए औद्योगिक पार्कों एवं एसईजेड की स्थापना की जा रही है।

चार विभागों ने दिए प्रजेन्टेशन

इंटेरेक्टिव सत्र में हुए प्रस्तुतीकरण में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध संरचना, शासन की ओर से सुविधाओं व औद्योगिक नीति के संबंध में चर्चा की। सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग डॉ. नवनीत कोठारी ने प्रदेश में एमएसएमई के लिए बन रहे क्लस्टर और विकास संभावनाओं की जानकारी दी। प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम टी. इलैया राजा ने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रजेन्टेशन दिया गया। सत्र में मध्यप्रदेश में रूचि रखने वाले कोयंबटूर सहित चैन्नई व तिरुपुर के निवेशकों ने सहभागीता की। कार्यक्रम में तिरुपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन, द सदर्न इंडियन मिल्स एसोसिएशन, द साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, इंडियन कॉटन फेडरेशन, द सदर्न इंडिया इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन,

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, इंडियन टेक्सटाइल फेडरेशन सहित 20 औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

तीन एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

इंटेरेक्टिव सत्र में 25 से अधिक उद्योगपतियों तथा 4 प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ वन-टू-वन बैठक की गई साथ ही राज्य के एक जिला-एक उत्पाद के संबंध में भी जानकारी का प्रसार किया गया। इसके साथ ही इंडियन कॉटन कारपोरेशन के साथ प्रदेश में इप्लएस कॉटन के उत्पादन और रकबे को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज शेयरिंग और प्रदेश में स्क्लड मैन पावर की उपलब्धता को बढ़ाने तथा टैक्सटाइल क्लस्टर स्थापित करने के लिए तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ नॉलेज शेयरिंग संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मप्र में कपास की खेती को बढ़ावा देने और रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट शेयरिंग के लिए साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन के साथ भी एमओयू हुआ।

पंचायत प्रतिनिधि एक गांव को आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी लें : प्रहलाद

पांच हजार से ज्यादा जनसंख्या वाली पंचायतों में बनेंगे दो सामुदायिक भवन

भोपाल(काप्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभी स्तरों की पंचायतों के पदाधिकारियों का आह्वान किया है कि वे अपनी पसंद के किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न योजनाओं में आपसी समन्वय के साथ एक मॉडल विलेज बनाएं।

श्री पटेल ने कहा कि अपने सपनों का गांव बनाने की शुरुआत करें। श्री पटेल आज यहां आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मप्र विषय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जर्मन संस्था जीआईजेड द्वारा आयोजित कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जो पंचायतें शहरों से से लगी हैं उनकी अपनी समस्याएं और मुद्दे होते हैं। वे अधशहरी कहलाती हैं। ऐसी 1200 पंचायतें हैं। इनके अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सदस्यों और अधिकारियों के साथ भी जल्दी ही

चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार पेसा पंचायतों और वन संरक्षित क्षेत्रों के समीप स्थित पंचायतों की स्थिति सामान्य पंचायतों से भिन्न है। उनके मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। श्री पटेल ने कहा जिन पंचायतों की जनसंख्या 5000 से ज्यादा है वहां दो सामुदायिक भवन बनाये जायेंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे उचित निर्माण स्थल का चयन करने की कार्यवाही शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों के पदाधिकारी जनपद पंचायतों की बैठकों में परामर्शदाता की भूमिका निभा सकते हैं लेकिन निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करें। पंचायत मंत्री ने कहा कि सभी पंचायतों के पदाधिकारी बैठकों के नियम की जानकारी रखें। इससे टकराव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंचायतों में की जा रही विकास की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखें ताकि समय पर उनमें सुधार हो सके।

कटनी में बाढ़ की स्थिति से निपटने के अधिकारियों को दिए निर्देश

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी जिले में अतिवृष्टि के कारण कई स्थानों पर जल भराव की दशा में जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कटनी जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कटनी जिला प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ, होमगार्ड के जवान और पुलिस प्रशासन टीम की तत्काल तत्परतापूर्वक सहायता ली जाए। उन्होंने सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उन्हें हर संभव मदद करने के निर्देश भी दिए हैं।

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था, दिशा-निर्देश जारी

भोपाल(काप्र)।

स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि जिन रिक्तियों के विरूद्ध शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के लिये अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पद के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक शासकीय विद्यालय में नहीं रखा जा सकेगा। निर्देशों में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में रिक्त पद है, वहां उन्हीं शिक्षकों को

नियमानुसार रखा जायेगा। इसमें हार्डकोर की गाईडलाइन का पालन किया जायेगा। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैल का स्कोर कार्ड जनरेट है, केवल उसी पैल में ज्वॉइनिंग दर्ज हो सकेगी। वर्ष 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है, उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगइन आईडी से ज्वॉइनिंग दे सके वह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वॉइनिंग अपने संबंधित विद्यालय में 7 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से देंगे। यह निर्देश विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिये जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्त पदों का प्रदर्शन 30 जुलाई 2024 तक किया जायेगा। अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज करना पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य

एक अगस्त से 7 अगस्त 2024 तक होगा। इसी अवधि में शाला प्रभारी ज्वॉइन किये गये अतिथि शिक्षक की उपस्थिति का प्रमाणीकरण करेंगे। ऐसी शाला में जहां नियमित शिक्षक पदस्थ है, लेकिन किन्हीं कारणों से सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिये अनुपलब्ध है। वहां अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने समय सारणी जारी की है। एक अगस्त से 4 अगस्त 2024 तक संकुल प्राचार्य द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड की जायेगी। 5 और 6 अगस्त को संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्लेन्ट का परीक्षण कर संचालनालय से अनुमोदन दिया जायेगा। 6 एवं 7 अगस्त को अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज कर सकेंगे।

मंत्री टेटवाल ने ग्लोबल स्किल पार्क का किया औचक निरीक्षण

भोपाल(काप्र)।

कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री गौतम टेटवाल ने संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से रू-ब-रू चर्चा की।

विद्यार्थियों के ट्रेड एवं ट्रेड की भविष्य में उपयोगिता के बारे में विस्तृत चर्चा की। श्री टेटवाल ने जीएसपी के हॉस्टल में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने मंत्री श्री टेटवाल को अपने मध्य पाकर खुशी के साथ ट्रेनिंग एवं संस्थान की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। श्री टेटवाल ने क्लास रूम, कॉफ़ेस हॉल सहित सम्पूर्ण परिसर का निरीक्षण किया। पार्क में प्रदेश से आये विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं। सिंगापुर से ट्रेनिंग लेकर आये प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के दल ने जीएसपी का भ्रमण किया। दल ने व्यवस्थाओं की सराहना की। दल ने जीएसपी के विभिन्न एडवांस



ट्रेड्स में स्क्लड मैनपावर से संभावित सहयोग लेने और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। दल में अतिरिक्त

महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (युद्धपोत परियोजनाएं) रियर एडमिरल इकबाल सिंह ग्रेवाल, डीजीक्यूए टीम में कैप्टन आरएस मिश्रा, कैप्टन ओपी शर्मा, कमांडर एमपीएस अजरोत और जे सिंह एसएसओ-2 भी शामिल थे। ग्लोबल स्किल पार्क के सीईओ आर रामलिंगम और परियोजना निदेशक गौतम सिंह ने नौसेना दल के अधिकारियों को पार्क की व्यवस्थाओं से अवगत कराया। रियर एडमिरल ने ग्लोबल स्किल पार्क में परीक्षण सुविधा एवं संचालित होने वाले कोर्सेस, एडवांसड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एडवांसड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, एडवांसड इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांसड नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांसड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, एडवांसड मेकैट्रॉनिक्स, एडवांसड एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, एडवांसड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, एडवांसड प्रिंसीपल इंजीनियरिंग (नौ सेना से संबंधित) स्थापित करने में रुचि व्यक्त की, जो उद्योग और छात्रों दोनों के लिए बहुत उपयोगी होगी।

नवाचार, शोध और अनुसंधान के केंद्र बनेंगे विश्वविद्यालय: परमार



भोपाल(काप्र)।

उच्च शिक्षा मंत्री इन्द्र सिंह परमार ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर स्थित ज्ञान विज्ञान भवन में भारतीय ज्ञान परंपरा और शोध अनुसंधान विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध कार्यशाला में कहा कि भारत का ज्ञान विश्व मंच पर सबसे पुरातन और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यह ज्ञान परम्परा एवं मान्यता के रूप में भारतीय समाज में सर्वत्र विद्यमान है।

शोध एवं अनुसंधान के आधार पर भारतीय ज्ञान परम्परा एवं मान्यता स्थापित हुई हैं। हर विधा-हर क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परम्परा के युगानुकूल एवं वर्तमान वैश्विक आवश्यकता अनुरूप, पुनः शोध एवं अनुसंधान कर दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है। शिक्षा में भारतीयता के भाव के समावेश और समाज में श्रेष्ठ नागरिक निर्माण के लिए भारतीय ज्ञान परम्परा को शिक्षा में समाहित करने के लिये कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन

प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और अत्यंत उपयोगी है। श्री परमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परम्परा समावेशी शिक्षा के आलोक पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020भारत को स्वत्व के भाव के साथ विश्वमंच पर सिरमौर बनने के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए हमें अपने गौरवशाली इतिहास, शौर्य, पराक्रम एवं उपलब्धियों पर गर्व का भाव जागृत करने की आवश्यकता है।

श्री परमार ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में विश्व को भारत पर गर्व है। विश्वभर के भारतवंशी, भारत को संकल्पों के साथ प्रगतिपथ पर आगे बढ़ता देख गौरवान्वित हैं। हमें भी देश की श्रेष्ठ परम्पराओं, त्याग एवं बलिदान आदि से प्रेरणा लेकर, विश्वगुरु भारत की संकल्पना को साकार करने में सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत के पुरातन ज्ञान को नूतन संदर्भ में शिक्षा में समावेश करने की आवश्यकता है। शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय ज्ञान परम्परा पर शोध और अनुसंधान के लिए वातावरण तैयार करना होगा।

महापौर, विधायक व निगमाध्यक्ष ने झांकी निर्माण हेतु किया भूमिपूजन

भोपाल(काप्र)।



बिट्टन मार्केट हॉट बाजार व्यापारी संघ द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर स्थापित होने वाली नवरात्रि झांकी हेतु भूमिपूजन किया। भूमिपूजन अवसर पर पूर्व सांसद आलोक संजय के अलावा विकास वीरानी, सुनील पांडे, व्यापारी संघ के अध्यक्ष हरिओम खटीक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन व आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे।

विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में...

मप्र की बाघ प्रिंट हस्तकला का सजीव प्रदर्शन

भोपाल(काप्र)। नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के भारत मंडप में आयोजित 46वें सत्र में मध्यप्रदेश के शिल्पगुरु श्री मोहम्मद युसुफ खत्री और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्री मोहम्मद बिलाल खत्री विख्यात बाघ प्रिंट हस्तकला का सजीव प्रदर्शन कर रहे हैं। विदेशी प्रतिनिधियों और अन्य आगंतुकों को वे बाघ प्रिंट की बारीकियां समझा रहे हैं। सत्र में विदेशी प्रतिनिधि अपने हाथों से बाघ ठप्पा छपाई का अनुभव कर रहे हैं और छपाई के सैपल को अपने साथ अपने देश लेकर जा रहे हैं। सत्र के सभी प्रतिभागियों को बाघ प्रिंट के परिधान बहुत लुभा रहे हैं और वे बाघ प्रिंट विरासत को संजोने में युसुफ खत्री और बिलाल खत्री के योगदान की प्रशंसा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति का 46वें सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत में आयोजित हो रहा है, जिसमें 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सत्र में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 'अतुल्य भारत' प्रदर्शनी लगाई गई है।